

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 05 जून 2008

विषय:- मै0 विदूर इन्टरप्राइजेज को औद्योगिक प्रयोजन (रासायनिक उत्पादन) की स्थापना हेतु जनपद उधमसिंहनगर की तहसील गदरपुर के ग्राम विजयनगर में कुल 0.475 है0 भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 72/सात-स0भू0अ0/2006 दिनांक 26, अक्टूबर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 विदूर इन्टरप्राइजेज को औद्योगिक प्रयोजन (रासायनिक उत्पादन) की स्थापना हेतु की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील गदरपुर के ग्राम विजयनगर के खाता सं0-239 के खेत नं0-1056 मध्ये 0.478 है0 (शमशान भूमि 0.003 है0 को छोड़कर) में से कुल 0.475 है0 भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2- केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह

ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- यह स्वीकृति 180 दिनों के लिये वैध होगी एवं भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 180 दिन के भीतर योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा।

7- प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पॉट जोनिंग क्षेत्र के लिये निश्चित सिद्धान्त/ नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

8- इकाई द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग नमक का पानी (रासायनिक उत्पाद) की स्थापना के लिये किया जायेगा।

9- प्रस्तावित कय की जाने वाली भूमि का भू- उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं उपलब्धियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10- प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) के अन्तर्गत GIDCR - 2005 में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।

11- प्रस्तावित उद्योग में 70 प्रतिशत रोजगार (नियमित रूप से) उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को ————— उपलब्ध कराया जायेगा।

12- इकाई में पूंजी निवेश एवं उद्योग स्थापना से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, तथा अग्निशमन आदि विभागों से नियमानुसार स्वीकृति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।

13- प्रस्तावित इकाई के उत्पाद भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 7 जनवरी, 2003 में थ्रस्ट उद्योग के अन्तर्गत एजेक्चर-2 में उल्लिखित थ्रस्ट उद्योगों के क्रियाकलापों में सम्मिलित नहीं है अतः प्रस्तावित उत्पाद के घोषित /अधिसूचित औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र से बाहर विनिर्माण पर इकाई का प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

- 14- किसी दशा में क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाये।
- 15- वर्तमान में यह स्वीकृति मात्र भूमि कय व्यवस्था के संदर्भ में है। भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 16- उपरोक्त के अतिरिक्त वांछित, विधिक व अन्य औपचारिकतायें / अनुज्ञायें / प्रमाण पत्र एवं अनापत्तियां इकाई स्थापना के पूर्व यथासमय प्राप्त कर ली जायेंगी।
- 17- उपरोक्त शर्तों / प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
 - 2- आयुक्त, कुमायू मण्डल, नैनीताल।
 - 3- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 4- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 5- सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 6- निदेशक, उद्योग, इन्ड्रिस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
 - 7- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2-न्यूकैन्ट रोड, सिडकुल, देहरादून।
 - 8- श्री किशोर भाटिया, पुत्र स्व0 श्री धनश्याम दास भाटिया नि0-855, बेलकम हाऊस, शाहदरा दिल्ली-110053
 - 9- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
 - 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

१